Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

दिसंबर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपा 3
- राजस्थान की दिव्यांग सुनीता गुप्ता और प्रशांत अग्रवाल को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 4
- रोगियों को सुरक्षित एवं सुगम रक्त आपूर्ति के लिये बनेगा एक्शन प्लान 5
- राजस्थान के सबसे लंबे हाईलेवल ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू 5
- राजस्थान गृह रक्षा विभाग के 2 अधिकारियों, 5 कार्मिकों तथा एक स्वयं सेवक को 'महानिदेशक प्रशस्ति-पत्र एवं डिस्क' से सम्मानित करने की घोषणा 6
- रावत एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक नरेंद्र सिंह रावत 'डायरेक्टर ऑफ द ईयर-2023' अवॉर्ड से सम्मानित 7
- बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आगाज 11 जनवरी से 8
- अलवर के गौरव यादव को मिला आईएमए का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 9
- प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में किया गया 'नो बैग डे' पर 'लैब डे' का आयोजन 10
- भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री 10
- एसआईटी एवं एंटी गैंगेस्टर टास्क फ़ोर्स का गठन 11
- लखपति दीदी सम्मेलन 11
- व्यापार सुगमता संबंधी सुधार 12
- प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालीचरण सराफ ने ली शपथ 13
- मुख्यमंत्री ने वेदांता पिंकसिटी हॉफ मैराथन का किया फ्लैग ऑफ 14
- राजस्थान ने युवा इंटर्नशिप योजना समाप्त कर दी 15
- गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 15
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये कॉन्टिनजेंसीय प्लान (आकस्मिक योजना) की विफलता 16

The Vision

नोट :

राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपा

चर्चा में क्यों?

3 दिसंबर, 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने और कॉन्ग्रेस की हार के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन पहुँचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र सौंपा।

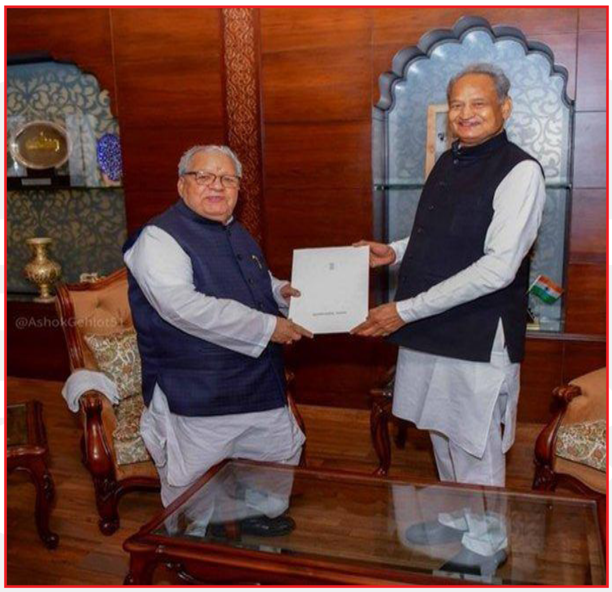

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल मिश्र ने तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए, उनसे राज्य में नई सरकार के गठन होने तक कार्य करते रहने का आग्रह किया।
- विदित हो कि राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 में भारतीय जनता पार्टी ने 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कॉन्ग्रेस को 69, जबकि अन्य पार्टियों और निर्दलियों को कुल 15 सीटें मिलीं।
- अशोक गहलोत 7वीं लोकसभा (1980-84) के लिये वर्ष 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र का 8वीं लोकसभा (1984-1989), 10वीं लोकसभा (1991-96), 11वीं लोकसभा (1996-98) तथा 12वीं लोकसभा (1998-1999) में प्रतिनिधित्व किया। 1998 में वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने।
- सरदारपुरा (जोधपुर) विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद गहलोत फरवरी, 1999 में 11वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। गहलोत इसी विधानसभा क्षेत्र से 12वीं और 13वीं राजस्थान विधानसभा के लिये पुनः निर्वाचित हुए। वे 14 और 15वीं राजस्थान विधानसभा में भी निर्वाचित हुए व मुख्यमंत्री बने।
- उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पी.वी. नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। वे तीन बार केंद्रीय मंत्री बने। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं, तब अशोक गहलोत 2 सितंबर, 1982 से 7 फरवरी, 1984 की अवधि में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री रहे। इसके बाद गहलोत खेल उपमंत्री बने।

नोट :

- 31 दिसंबर, 1984 से 26 सितंबर, 1985 की अवधि में गहलोत ने केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात् उन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। गहलोत इस मंत्रालय के 21 जून, 1991 से 18 जनवरी, 1993 तक मंत्री रहे।

राजस्थान की दिव्यांग सुनीता गुप्ता और प्रशांत अग्रवाल को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

3 दिसंबर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में राजस्थान की दिव्यांग सुनीता गुप्ता और प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार-2023 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिये विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिये देशभर से 21 व्यक्तियों और 9 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार-2023 प्रदान किया।
- दौसा की 70% गतिविषयक दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये 'सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन' की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार-2023 से सम्मानित किया गया है।
  - दिव्यांग सुनीता गुप्ता ग्रामीण क्षेत्र से होने के बावजूद, उन्होंने सरकार से 50 हज़ार रुपए का ऋण लेकर कृत्रिम आभूषण का व्यवसाय शुरू किया।
  - वे वर्षा जल संचयन मिशन और स्वीप टीम मतदाता जागरूकता से भी संबद्ध हैं। उन्होंने विक्की डोनर फिल्म में भी काम किया है।
- नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के अध्यक्ष 51 वर्षीय प्रशांत अग्रवाल द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्य के लिये उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति-दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये कार्यरत' श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार-2023 से सम्मानित किया गया है।
  - प्रशांत अग्रवाल आवासीय विद्यालयों, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के नि:शुल्क वितरण, संगठन के माध्यम से नि:शुल्क विवाह समारोहों जैसी पहलों के माध्यम से दिव्यांगजनों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं।
  - वर्ष 2017 में उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ता से भी सम्मानित किया गया है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1969 में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के रूप में उत्कृष्ट दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना को मंज़ूरी दी थी। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किये गए हैं।
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को उत्कृष्ट दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये काम करने वाले व्यक्तियों/संगठनों को 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' पर प्रदान किये जाते हैं।
- वर्ष 2023 के लिये विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के तहत गए हैं-

I. विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार-2023-व्यक्तिगत उत्कृष्टता

- सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन
- श्रेष्ठ दिव्यांगजन
- लोकोमोटर चुनौती - (लोकोमोटर, मांसपेशीय चुनौतियाँ, बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम, कुष्ठ रोग से उबरे हुए, सेरेब्रल पाल्सी)
- दृश्य हानि - (अंधापन, कम दृष्टि)
- श्रवण हानि (बहरा, सुनने में कठिनाई, बोलने और भाषा की चुनौती)
- बौद्धिक विकलांगता (मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट सीखने की चुनौती, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार)
- उपरोक्त उल्लिखित विकलांगताओं को छोड़कर कोई भी निर्दिष्ट विकलांगता।
  - श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका
  - सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति - दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये कार्यरत्
  - सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर (पुनर्वास पेशेवर/कार्यकर्त्ता) - दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत्

II. दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार-2023

- दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ)
- दिव्यांगों के लिये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता - (सरकारी संगठन/पीएसई/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)
- सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधामुक्त परिवेश के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/यूटी/ज़िला
- सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सरकारी/निजी संगठन)
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/यूटी/ज़िला
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अपने राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त
- पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन

रोगियों को सुरक्षित एवं सुगम रक्त आपूर्ति के लिये बनेगा एक्शन प्लान

चर्चा में क्यों?

4 दिसंबर, 2023 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि प्रदेश में रोगियों को रक्त एवं रक्त अवयवों (प्लाज़्मा, प्लेटलेट्स, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, क्रायोप्रोसिपिटेट) की सुगम एवं सुरक्षित उपलब्धता के लिये एक्शन प्लान बनाया जाएगा एवं दो उप-समितियाँ (रेगुलेटरी एवं टेक्नीकल) गठित की जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- शुभ्रा सिंह ने शासन सचिवालय में राज्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज एवं राज्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए।
- ये कमेटियाँ प्रदेशभर में ब्लड बैंकों का भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगी।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में रोगियों को सुगमतापूर्वक एवं सुरक्षित रूप से रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिये जल्द एक्शन प्लान बनाया जाए। उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये एक स्टेट नोडल ऑफिसर नियुक्त करने एवं जोनल स्तर पर संबंधित मेडिकल कॉलेज की जोन स्तरीय कमेटी द्वारा नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश दिए।
- उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में स्थापित सभी ब्लड बैंकों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कोई भी ब्लड बैंक निर्धारित प्रोटोकॉल या गाइडलाइन का उल्लंघन करे तो सख्त कार्रवाई की जाए।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आम नागरिक तक रक्त की सुगम आपूर्ति के लिये
- ई-रक्त कोष पोर्टल के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल एवं 181 हैल्पलाइन के माध्यम से भी इस संबंध में आमजन को जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।

राजस्थान के सबसे लंबे हाईलेवल ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू

चर्चा में क्यों?

5 दिसंबर, 2023 को पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि सवाई माधोपुर-इटावा मार्ग पर झरेर के बालाजी केतुदा गाँव के पास चंबल नदी पर राजस्थान के सबसे लंबे हाईलेवल ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि यह हाईलेवल ब्रिज 165 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी लंबाई 1880 मीटर होगी।
- इसका निर्माण होने से राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के लोगों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा खातोली, इटावा, बारां ज़िले से सवाई माधोपुर का सीधा जुड़ाव हो जाएगा।

नोट :

- वर्तमान में चंबल नदी पर बना गैंता माखीदा का ब्रिज प्रदेश में सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी लंबाई करीब 1562 मीटर है। यह भी पूर्व में इटावा क्षेत्र में बना था। यह ब्रिज कोटा ज़िले के साथ ही भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर को भी जोड़ेगा।
- राज्य सरकार ने पिछले साल बजट घोषणा में झरेर के बालाजी ब्रिज की डीपीआर निर्माण के लिये 30 लाख रुपए जारी किये थे। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसकी 165 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर जयपुर भिजवाई थी। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी।
- मुकेश मीणा ने बताया कि यह प्रेस्ट्रस्ड कंक्रीट गर्डन ब्रिज होगा। इसमें चार गर्डर होंगे। वहीं 12 मीटर चौड़े पुल में साढ़े सात मीटर का केरीज-वे होगा। पुल से सवाई माधोपुर की तरफ 280 मीटर एप्रोच सड़क भी बनेगी। इस प्रकार कोटा की तरफ 486 मीटर की एप्रोच सड़क बनेगी। इसमें दो छोटे छोटे माइनर पुल भी बनाए जाएंगे।
- ब्रिज के निर्माण में 48 पिल्लर खड़े किये जाएंगे। इसमें दोनों तरफ दो अबेटमेंट भी होंगे, जो सवाई माधोपुर और कोटा की तरफ पुल की शुरुआत में बनेंगे। इन 48 पिलरों पर हर पिलर के बीच 40 मीटर लंबे स्थान रखे जाएंगे। इसमें चट्टान के ऊपर पाँच पिलर बनेंगे और साथ बेल फाउंडेशन वाले होंगे। इसके अलावा 36 पायल फाउंडेशन बनाए जाएंगे, जो मिट्टी और चट्टानों पर बनते हैं। इनमें दो अबेटमेंट शामिल हैं।

राजस्थान गृह रक्षा विभाग के 2 अधिकारियों, 5 कार्मिकों तथा एक स्वयं सेवक को 'महानिदेशक प्रशस्ति-पत्र एवं डिस्क' से सम्मानित करने की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2023 को 61वें गृह रक्षा स्थापना दिवस-2023 की पूर्व संध्या पर राजस्थान गृह रक्षा विभाग के 2 अधिकारियों, 5 कार्मिकों तथा एक स्वयं सेवक को महानिदेशक गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'महानिदेशक प्रशस्ति-पत्र एवं डिस्क' से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- विभाग के सीनियर स्टाफ ऑफिसर नवनीत जोशी ने बताया कि राजस्थान गृह रक्षा विभाग के समादेष्टा विकास लांबा, उप-समादेष्टा रवींद्र सिंह, कंपनी कमांडर बलवीर सिंह, रघुनाथ सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भंवर विरेंद्र सिंह, प्लाटून कमांडर नारणाराम, वरिष्ठ सहायक मदन मोहन जोशी एवं स्वयं सेवक भगवत सिंह को यह अवार्ड दिया जाएगा।

- इसी प्रकार महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राजस्थान द्वारा विभाग में की गई सराहनीय सेवाओं के लिये समादेष्टा विकास लांबा, उप-समादेष्टा रामजीलाल एवं ललित बिहारी, कंपनी कमांडर गंगा सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राम प्रकाश सिंह, प्लाटून कमांडर देशराज एवं शुभकरण शर्मा, स्वयं सेवक दिनेश डामोर, गौतम गहलोत, मोहम्मद अफजल, उम्मेद सिंह एवं स्वर्गीय संतोष कुमार मुद्गल को 'महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क' एवं महानिदेशक प्रशस्ति-पत्र दिये जाने की घोषणा की गई है।

रावत एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक नरेंद्र सिंह रावत 'डायरेक्टर ऑफ द ईयर-2023' अवॉर्ड से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2023 को होटल क्लार्क आमेर में आयोजित सम्मान समारोह में यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन के द्वारा रावत एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक नरेंद्र सिंह रावत को 'डायरेक्टर ऑफ द ईयर-2023' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में अमेरिका से आई इंडसेज इंटरनेशनल की फाउंडर एलिजाबेथ टेलर ने सभी शिक्षाविदों को अवॉर्ड से सम्मानित किया। इसमें शिक्षा जगत के विभिन्न दिग्गजों को सम्मानित किया गया।
- नरेंद्र रावत इससे पूर्व भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिये कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज की ओर से एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड प्रमुख है।
- शिक्षाविद् होने के साथ-साथ रावत समाजसेवी और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अक्षेंद्र वेलफेयर सोसायटी के सचिव हैं।
- विदित हो कि यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन, 2019 में स्थापित, एक अत्याधुनिक अनुसंधान-आधारित मीडिया संगठन है, जो शिक्षा, बीएफएसआई, मानव संसाधन और विपणन क्षेत्रों में क्रांति लाने पर केंद्रित है।

बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आगाज 11 जनवरी से

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2023 को बीकानेर के कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 11 से 14 जनवरी तक होगा।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इस बार 'आइकंस ऑफ बीकानेर' की थीम पर ऊँट उत्सव आयोजित होगा। इसमें स्थानीय कला, संगीत और संस्कृति में विशेष उपलब्धियाँ हासिल करने वाले कलाकारों को उत्सव के माध्यम से एक वैश्विक मंच उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ऊँट उत्सव में 11 जनवरी को क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स के संबंध में विशेष आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शास्त्रीय संगीत व शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकारों द्वारा विशेष प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी।
- उत्सव के दौरान 12 जनवरी को धरणीधर स्टेडियम में कला व संस्कृति का फ्यूजन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोक कला संस्कृति के रंगों के साथ-साथ कंटेंपरेरी आर्ट भी जोड़कर आयोजित होगा। स्थानीय व्यंजन भी इस शो के आकर्षण रहेंगे।
- ज़िला कलेक्टर ने बताया कि कैमल फेस्टिवल के दौरान काइट फ्लाइंग कंपटीशन का आयोजन भी किया जाएगा। मेले के दौरान प्रतिदिन शहरी परकोटे में पैदल वॉक और तांगा राइड, हवेली संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।
- सहायक निदेशक पर्यटन कृष्ण कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव के दौरान रायसर में सेलिब्रिटी नाइट आयोजित की जाएगी, जिसमें अग्नि नृत्य के साथ-साथ एक विशेष सेलिब्रिटी को प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि रायसर के घोड़ों में घुड़दौड़ और घोड़ों के नृत्य भी इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव में आकर्षण के विशेष केंद्र होंगे। कैमल फार्म में प्रतिवर्ष की भांति ऊँट दौड़ आयोजित होगी। कैमल फार्म में ऊँट श्रृंगार प्रतियोगिता ऊँट दौड़ प्रतियोगिता ऊँट डाँस प्रतियोगिता एवं ऊँट पर कटिंग प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएगी।

नोट :

अलवर के गौरव यादव को मिला आईएमए का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2023 को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) देहरादून में पासिंग आउट परेड में राजस्थान के अलवर ज़िले के गौरव यादव को आईएमए का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' मिला, साथ ही वे गोल्ड मैडल विजेता भी रहे।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से 343 युवा कैडेट्स पास आउट होकर देश सेवा के लिये सेना की मुख्यधारा में जुड़ गए। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए।
- पासिंग आउट परेड में गौरव यादव को ऑर्डर ऑफ मैरिट में पहला स्थान मिलने पर गोल्ड मैडल मिला। चमोली, उत्तराखंड के सौरव बधानी को ऑर्डर ऑफ मैरिट में दूसरा स्थान मिलने पर सिल्वर मैडल तथा कानपुर, उत्तर प्रदेश के आलोक सिंह को तीसरा स्थान मिलने पर ब्रॉन्ज मैडल मिला।
- विदित हो कि अलवर के गौरव यादव के पिता बलवंत सिंह यादव किसान हैं और माँ कमलेश यादव गृहणी हैं। गौरव ने केरल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी। उनके भाई विनीत कुमार सेना में नायक के पद पर कार्यरत हैं।
- गौरव ने बताया कि उन्होंने पाँच बार एनडीए की परीक्षा दी। चार बार वह असफल रहे, लेकिन पाँचवीं बार एनडीए पास किया। उन्हें पिछले साल अकादमी के 143वें कोर्स में राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक (प्रेसीडेंट गोल्ड मेडल) मिला था।

नोट :

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में किया गया 'नो बैग डे' पर 'लैब डे' का आयोजन

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2023 को राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 'नो बैग डे' की एक्टिविटी के तहत 'लैब डे' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के व्यवस्थित, नियमित, सुचारू एवं प्रभावी संचालन से विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में निखार लाने के लिये 'लैब डे' के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- इस अवसर पर विभाग के राज्य, संभाग, ज़िला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा विद्यालय की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, जीवविज्ञान, कंप्यूटर लैब, गृह विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा की लैब (प्रयोगशालाओं) का अवलोकन किया गया।
- इस अवसर पर विभाग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप लैब्स को बहुत ही अच्छी प्रकार व्यवस्थित किया गया। रासायनिक पदार्थों पर लेबलिंग की गई। रसायन विज्ञान व भौतिक विज्ञान के प्रयोगों को करने में विद्यार्थियों ने विशेष रुचि प्रदर्शित की। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य, सांइस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया गया।
- शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि नो बैग डे के अवसर पर 'लैब डे' मनाने का उद्देश्य, प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रभावी शिक्षण एवं विद्यार्थियों के लिये सीखने के अवसरों में वृद्धि करना है।

भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2023 को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक में जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडेय की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था।

नोट :

- विधायक दल की बैठक में जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक दीया कुमारी और जयपुर के दुदू सीट से विधायक प्रेम चंद्र बैरवा को उप-मुख्यमंत्री चुना गया। अजमेर उत्तर से लगातार पाँचवीं बार विधायक बने वासुदेव देवनानी को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा।
- राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। नई सरकार 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेगी।
- 56 साल के भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं और पहली बार विधायक बनकर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। वे भाजपा के प्रदेश महासचिव भी हैं।
- विदित हो कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक राजस्थान में 13 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भजन लाल शर्मा 14वें मुख्यमंत्री होंगे।
- राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अशोक गहलोत के नाम दर्ज है। वे लगातार 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे लंबे कार्यकाल में दूसरे नंबर पर मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं।
- राजस्थान में वर्ष 1949 से अब तक 25 बार सरकार का गठन हुआ, जिसमें 20 बार कॉन्ग्रेस, 4 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा अब पाँचवीं बार सत्ता संभालने जा रही है। अब तक तीन बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है।

एसआईटी एवं एंटी गैंगेस्टर टास्क फ़ोर्स का गठन

चर्चा में क्यों?

17 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष जांच दल एवं एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है|

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की रोकथाम एवं त्वरित जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है|
- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं) वी के सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है।
- इसके साथ ही राज्य में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (Anti Gangster Task Force) का गठन किया गया है|
- राज्य स्तर पर एक विशेष कार्य दल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन के नेतृत्व में किया गया है।
- यह दल मानवीय व तकनीकी आसूचना संकलन कर संगठित अपराध करने वाले गिरोह की पहचान करेगा और उनका डाटाबेस तैयार कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर गैंगस्टर को सख्त सजा दिलवाने का कार्य करेगा।
- इस जांच दल में एक एडीजी, एक-एक आईजी/ डीआईजी/एसपी, चार एडिशनल एसपी, आठ डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर/ एसआई, 10 एएसआई/ हेड कांस्टेबल एवं 15 कांस्टेबल तथा कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 50 लोग शामिल किए गए हैं।

पैटर्न रणनीति पाठ्यक्रम संग्रह FAQS राज्य विशिष्ट जानकारी

लखपति दीदी सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

23 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में 'लखपति दीदी सम्मेलन' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 2 करोड़ माताओं-बहिनों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नोट :

- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाया जा चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 150 करोड़ रुपए के चैक भी वितरीत किए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए 1,000 करोड़ रूपए के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण एसएचजी मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 2 लाख नई महिला सदस्यों को एसएचजी से जोड़ने का लक्ष्य है और उन्हें सरल ऋण सुविधाएं व मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
- उन्होंने कहा कि एसएचजी में काम करने वाली लगभग 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से न्यूनतम दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हर ज़िले में एक महिला थाना स्थापित किया जाएगा। हर पुलिस थाने में महिला डेस्क की स्थापना होगी तथा सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन भी होगा।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी योजना के माध्यम से आने वाले समय में प्रदेश की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होंगी। इस पहल से महिलाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें आजीविका के नवीन साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

व्यापार सुगमता संबंधी सुधार

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित "व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस)" सुधारों को सफलतापूर्वक आरम्भ करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। इस प्रकार, राज्य खुले बाज़ार की उधारियों के जरिए 2,731 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र बन गया है।

मुख्य बिंदु:

- सूची में राजस्थान पाँच अन्य राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया है,
- व्यवसाय करने की सुगमता देश में निवेश अनुकूल वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- भारत सरकार ने मई 2020 में, उन राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमतियों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया, जिन्होंने व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सुधार आरम्भ किए। इस श्रेणी में निर्धारित सुधार निम्नलिखित हैं:
    - 'ज़िला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना' का प्रथम मूल्यांकन पूरा करना।

- ‘जिला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना’ के प्रथम आकलन की पूर्णता
- विभिन्न अधिनियमों के तहत व्यवसायों द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों/अनुमोदनों/लाइसेंसों के नवीकरण की वांछनीयता का उन्मूलन।
- अधिनियमों के तहत कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन।

- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधार सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। इस विशेष व्यवस्था का आधा हिस्सा राज्यों द्वारा लोक केंद्रित सुधारों से जोड़ दिया गया। चिन्हित सुधारों के लिए चार लोक केंद्रित क्षेत्र थे-
  - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन
  - व्यवसाय करने की सुगमता सुधार
  - शहरी स्थानीय निकाय/जनोपयोगी सेवा सुधार और
  - विद्युत क्षेत्र सुधार।

नोटः

खुले बाज़ार उधारियों (OMB) कॉरपोरेट्स या सरकारी संस्थाओं द्वारा जनता को बांड, डिबेंचर या ट्रेजरी बिल जैसी प्रतिभूतियाँ जारी करके धन जुटाने की एक विधि है।

- ये प्रतिभूतियाँ खुले बाज़ार में जारी की जाती हैं, जो निवेश करने में रूची रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदने के लिये उपलब्ध हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत में OMBs को नियंत्रित करता है।

प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालीचरण सराफ ने ली शपथ

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी, वासुदेव देवनानी,उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा सहित अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहे।
- राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनके सहयोग के लिये वरिष्ठ विधायकों का एक तीन सदस्य पैनल भी बनाया गया है। इस पैनल में विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी

- डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का शामिल है।
- विदित हो कि प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। पार्टी पहले ही वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष नामित कर चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ प्रोटेम स्पीकार ही दिलाता है। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। स्थायी विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के पदभार ग्रहण करने के साथ ही प्रोटेम स्पीकार का कार्य और कार्यकाल स्वत: समाप्त हो जाता है।
- प्रो-टेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है 'कुछ समय के लिये'। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे सीमित अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है।
- प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता: लोकसभा/विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है।
- राष्ट्रपति/राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है.
- प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य:
  - प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है।
  - स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये मतदान कराना।
  - नए अध्यक्ष के चुनाव पर प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है।
  - वह फ्लोर टेस्ट का संचालन भी करते हैं।

मुख्यमंत्री ने वेदांता पिंकसिटी हॉफ मैराथन का किया फ्लैग ऑफ

चर्चा में क्यों?

17 दिसंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वस्थ भारत' के संकल्प को साकार करती वेदांता पिंकसिटी हॉफ मैराथन को फ्लैग ऑफ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को स्वस्थ और उत्साहित रहकर देश में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए।
- यह मैराथन 'रन फॉर जीरो हंगर' के महत्वपूर्ण उद्देश्य से हो रही है। इस आयोजन में 12 हज़ार से अधिक धावकों को एकजुट किया गया है। इससे एक लाख से अधिक जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- मैराथन में 21 कि.मी. की हाफ मैराथन, 10 कि.मी. की कूल रन और 5 कि.मी. की ड्रीम रन कैटेगरी में धावकों ने दौड़ पूरी कर फिटनेस और एकजुटता का संदेश दिया।

राजस्थान ने युवा इंटर्नशिप योजना समाप्त कर दी

चर्चा में क्यों ?

नवनिर्वाचित राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर 2023 से 'राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना' (RHYMES) को खत्म करने का फैसला किया है।

मुख्य बिंदुः

- वर्ष 2021-22 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य युवा स्नातकों को व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करना और उन्हें अपने कौशल तथा ज्ञान को विकसित करने में सहायता करना है।
- इसके तहत प्रशिक्षुओं को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में रखा गया तथा उन्हें 10,000 रुपए तक का वजीफा दिया गया।
  - इस कार्यक्रम के तहत लगभग 50,000 युवाओं को नामांकित किया गया था।
- अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के अनुसार, यह योजना राजीव गांधी युवा मित्र (RYM) नामक बौद्धिक एवं स्व-प्रेरित युवाओं का एक समूह विकसित करने हेतु लाई गई थी।
  - इस पहल का उद्देश्य लोगों को शासन के विषय में शिक्षित करना और सरकार में उनका विश्वास पैदा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें उनके दरवाजे पर पूरी हों।
- कुछ महत्त्वपूर्ण राज्य पहल योजनाएँ हैं:
  - मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना।
  - कौशल विकास पहल योजना (SDIS)।
  - पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।

गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जनवरी से बीपीएल कार्डधारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदुः

- सब्सिडी उन लाभार्थी महिलाओं के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत आती हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्डधारक है।
  - योजना का नाम अब इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना से बदलकर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है।
- लाभार्थी विकसित भारत संकल्प योजना में अपना पंजीकरण कराकर सस्ते सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

- यह योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू की गई थी।
- इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) द्वारा एक प्रमुख योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन जैसे ग्रामीण तथा वंचित परिवारों को LPG उपलब्ध कराना था, जो अन्यथा पारंपरिक रसोई ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले का उपयोग कर रहे थे।
  - पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये कॉन्टिनजेंसीय प्लान (आकस्मिक योजना) की विफलता

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017 में मसौदा समिति द्वारा तैयार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम-1995 के तहत कॉन्टिनजेंसीय प्लान (आकस्मिक योजना) को लागू करने में राज्य सरकार की विफलता को गंभीरता से लिया है।

- बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा सहित 15 राज्यों ने व्यापक आकस्मिक योजनाएँ तैयार कर उन्हें लागू किया है।

मुख्य बिंदु:

- एक गैर-सरकारी संगठन दलित मानवाधिकार केंद्र समिति (DMKS) ने भी 2017 में जाति-आधारित हिंसा के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, अतिरिक्त वित्तीय सहायता, गवाहों की सुरक्षा के प्रावधानों के साथ कॉन्टिनजेंसीय प्लान का एक ड्रॉफ्ट सौंपा था। वहीं पीड़ित की मदद के लिये निगरानी तंत्र विकसित करने की मांग की थी।
- DMKS द्वारा दायर एक जनहित रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिये एक कॉन्टिनजेंसीय प्लान बनाने का उद्देश्य अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन प्रक्रिया में देरी के कारण बाधित हो रहा है।
- वर्तमान में राज्य सरकार वर्ष 1995 के नियमों के नियम 12 (4) के तहत अत्याचार के पीड़ितों को राहत प्रदान करती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के सात दिनों के भीतर आर्थिक सहायता दी जाती है।
- वर्ष 1995 की नियमावली के नियम 15 के तहत लागू की जाने वाली आकस्मिक योजना में विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारी निर्दिष्ट होनी चाहिये।
- पैकेज में पीड़ितों को अनिवार्य रूप से मुआवजा, पुनर्वास, सरकारी रोज़गार और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मज़बूत करना शामिल होना चाहिये।